

खोजी खबरें-तेज नज़रें

प्रेरणा स्रोत - स्व. चुन्नीलाल सालवी

ये अखबार ही नहीं क्रांति का अभियान है। मानवता एवं लोकतंत्र का सजग प्रहरी, ये दुष्टों की मौत का सामान है।

वर्ष - 14 अंक - 22

14 जुलाई 2025, सोमवार

संपादक - दयाराम दिव्य

सहसंपादक - चाहत सालवी

मूल्य - 2 रु.

भीलवाड़ा में इनकम टैक्स की रेड: खुद को सीए बताकर भरता था रिटर्न

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा में एक व्यक्ति के घर आईटी की रेड पड़ी है, यह व्यक्ति खुद सीए बताकर लोगों के रिटर्न फाइल करता था। आज सुबह करीब 8 बजे के बाद आईटी की टीम इसके घर पर पहुंची और यहां डॉक्यूमेंट की चेकिंग की जा रही। फिलहाल मामला क्या है और कितनी प्रॉपर्टी से जुड़ा है इसकी डिटेल्स पता नहीं लगी है लेकिन जानकारी सूत्रों के मुताबिक किसी बड़े जमीनी घोटाले के मामले में टीम जांच करने पहुंची है।

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलजार नगर गली नंबर 5 का है। यहां रहने वाले राजेश खोईवाल के मकान पर आज सुबह आईटी टीम रेड डालने के लिए



पहुंची। राजेश खुद को सीए बताता था और लोगों के रिटर्न भरने का काम करता था साथ ही इनकम टैक्स के काम काज भी

देखता था।

आईटी टीम को इसके फर्जी काम करने की सूचना के साथ ही किसी बड़े जमीन घोटाले से जुड़ा

पूरा मामला बताया जा रहा है हालांकि इस मामले पर कोई भी आधिकारिक जानकारी डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दी गई।

मांडल में नाबालिग लड़कों से मारपीट के बाद गर्माया माहौल: होटल में घुसकर मारपीट और फेंके पत्थर

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में दो नाबालिग लड़कों के साथ मारपीट की घटना के बाद माहौल गरमा गया। एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लड़कों ने दो नाबालिग लड़कों पर हमला किया। जिसमें वो दोनों घायल हो गए।

घटना रविवार रात करीब 8 बजे हुई। मांडल कस्बे में रहने वाला विजय खटीक अपने मित्र धनराज तेली से मिलने सत्य नारायण मंदिर के पास पहुंचा, इस दौरान करीब आधा दर्जन लड़कों ने मिलकर दोनों पर हमला बोल दिया।

मारपीट के दौरान लात-धुंनों के साथ-साथ पत्थर और लकड़ी से भी वार किया गया। आरोपियों ने जानलेवा हमला करते हुए उनकी बाइक लात मारकर गिरा दी। पीड़ित पक्ष के अनुसार हमलावरों ने पीड़ित को गालियां देते हुए जातिसूचक



शब्दों का भी प्रयोग किया।

वे दोनों बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मौके भागे और पास की होटल में छिपे, लेकिन हमलावरों ने भी पत्थर व लकड़ी लेकर पहुंच गए।

होटल पर भी पत्थरबाजी की गई, जिससे भगदड़ मच गई। वहां मौजूद

भीड़ ने हस्तक्षेप कर पीड़ितों को किसी तरह बचाया, नहीं तो जान को गंभीर खतरा हो सकता था। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट देकर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

घटना से आक्रोशित कस्बेवासियों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। पुलिस

ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है।

विवाहिता ने ससुराल में फंदा लगाकर जान दी: एक महीने पहले ही हुई थी शादी



द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा में एक नव विवाहिता ने ससुराल में फंदा लगाकर जान दे दी। एक महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल सकता है। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप नहीं लगाए हैं लेकिन मामले की जांच की मांग की है। मामला जिले के मंगरोप थाना इलाके के मंडपिया स्टेशन इलाके का है। घटना रविवार शाम को हुई।

डिप्टी एसपी श्याम सुंदर ने बताया- महिला आशा (19) का पति प्रजापत पवन मटकी बेचने का काम करता है। कल शाम महिला ने ससुराल में ही घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजन ने बताया- आशा अपने कमरे में थी। कल शाम उसे काफी आवाज लगाई लेकिन जवाब नहीं दिया। उसे

बुलाने कमरे में गए तो वह छत के कुंदे से फंदा लगाकर लटकी हुई मिली। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवा कर शव को फंदे से उतरवाया और भीलवाड़ा जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया। पीहर पक्ष के लोगों को सूचना देकर बुलाया। पीहर वालों ने ससुराल पक्ष या दामाद पर कोई आरोप नहीं लगाया। सुसाइड के कारणों की जांच की मांग की है। आशा और पवन की शादी एक महीने पहले ही हुई थी। तहसीलदार की मौजूदगी में शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। मामले की जांच उपखंड अधिकारी नेहा छीपा कर रही हैं।

डॉंग को रोटी डालने पर झगड़ा, पति-पत्नी से मारपीट

कोटा शहर के अनंतपुर थाना क्षेत्र इलाके में ओम एनक्लेव सोसाइटी डॉंग को रोटी डालने पर विवाद हो गया। सोसाइटी में रहने वाले पिता-पुत्र ने एक महिला और उसके पति से बदतमीजी की। मामला बढ़ा तो गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और महिला के भी थप्पड़ जड़ दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

अनंतपुरा थाने में 13 जुलाई को पीड़िता ने बताया- सोसाइटी की महिलाएं 12 जुलाई की शाम को घूम रही थी। इतने में महेश मित्तल और उनका बेटा डब्लू मित्तल



आया। वह बदतमीजी करने लगा। मेरे पति भी आ गए। उनके कार से उतरते ही पिता-पुत्र ने उनके साथ गाली-गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। बीच-बचाव करने पर मेरे साथ मारपीट की थी। गालियां देकर बोलता रहा कि थाने में जाकर रिपोर्ट करवा दो, हमारी ही दादागिरी चलती है।

पुलिया पार करते समय दो युवक बहे: सिविल डिफेंस टीम ने बचाई जान; पलकी-रावी नदियां उफान पर

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

मूसलधार बारिश ने बिजौलिया कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों की रफ्तार पूरी तरह थाम दी है। रविवार रात से सोमवार दोपहर तक भी रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कस्बे से जुड़ने वाले तीनों प्रमुख मार्ग जलमग्न हो गए हैं, जिससे बिजौलिया का संपर्क अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह कट गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे तक पिछले 15 घंटों में 46 मिमी बारिश दर्ज की गई।

पुलिया पार करते समय दो युवक बहे, सिविल डिफेंस टीम

ने बचाई जान

सोमवार दोपहर करीब 12.15 बजे छाई बाढ़ की पुलिया पार करते समय दो युवक बह गए। सिविल डिफेंस टीम ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत से नीरज राजपूत निवासी बिजौलिया और कैलाश राजपूत निवासी खेराड़िया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टीम ने पहले नीरज को सुरक्षित निकाला, उसके बाद पेड़ में फंसे कैलाश को भी रेस्क्यू कर लिया गया। कोटा की ओर पार्श्वनाथ चौराहा बाई पर स्थित पुलिया पर पानी ओवरफ्लो होने से आवागमन बंद हो गया है। कैसरगंज की ओर बह रही पलकी नदी उफान पर है, जबकि छाई बाई



बालाजी के पास स्थित पुलिया पर करीब तीन फीट पानी भर जाने से

यह रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इन मार्गों के बंद होने से मालीपुरा

और अन्य गांवों का संपर्क टूट गया है। कई दोपहिया और चौपहिया वाहन पानी में फंसे हुए हैं। तेजाजी चौक पर भीलवाड़ा जाने वाली बसें जलभराव के कारण जाम में फंसी रहीं। पंचायत चौक से सब्जी मंडी तक की सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। पथिक पार्क तालाब में तब्दील हो गया है। हर गली-मोहल्ले में बारिश का पानी भर गया है, जिससे आमजन को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। पलकी और रावी नदियों में तेज बहाव है और मंडोल बांध पूरी तरह भरकर ओवरफ्लो हो गया है। भड़किया, सेवन फॉल और मेनाल जैसे झरनों में पानी पूरे वेग से बहता दिखाई दे

रहा है, जिससे क्षेत्र में सुंदर प्राकृतिक दृश्य बन गए हैं, लेकिन खतरा भी बढ़ गया है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे सोयाबीन, मक्का और उड़द जैसी खरीफ फसलों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों ने चिंता जताई है कि यदि बारिश यूं ही जारी रही तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो सकती हैं। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। विशेषकर पुलिया और तेज बहाव वाली नदियों के आसपास सतर्कता बरतने को कहा गया है। हालात पर नजर रखने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिया गया है।

सम्पादकीय

आर्थिकी के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड

आरबीआई द्वारा हाल में जारी किए बैंकिंग धोखाधड़ी के आंकड़े चिंतित करते हैं। इसके अनुसार देश में बैंकिंग धोखाधड़ी का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी की रकम 12,230 करोड़ रुपये थी, जो 2024-25 में करीब तीन गुना बढ़कर 36,014 करोड़ रुपये हो गई। इसमें सरकारी बैंकों में हुई धोखाधड़ी की राशि 25,667 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र के बैंकों में हुई धोखाधड़ी की राशि 10,088 करोड़ रुपये थी। आरबीआई के अनुसार इस वृद्धि का एक बड़ा कारण 2023 में सुप्रीम



कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 122 पुराने मामलों को जोड़ना है। हालांकि इससे बैंकों से गायब हुए 36,014 करोड़ रुपये की समस्या कम नहीं हो जाती। बैंकिंग धोखाधड़ी का प्रभाव वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं होता है। ये बैंकों में जनता के विश्वास को भी कम करते हैं। वर्ष 2016 में नए नोटों को प्रिंट करने के साथ आरबीआई ने दावा किया था कि इनमें जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, उनकी नकल करना काफी मुश्किल है, फिर भी यह नहीं रुक पा रहा है। 2024-25 में बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या में 200 और 500 रुपये की श्रेणी में क्रमशः 14 प्रतिशत और 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार और रिजर्व बैंक इसे रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए-नए उपाय किए जा रहे हैं, वैसे-वैसे ठग उनकी नकल करने की तकनीक भी विकसित करते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी के लिए नकली और असली नोटों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पाया है कि इन नकली नोटों को भारत भेजने के लिए नेपाल और पाकिस्तान के मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। ये नकली नोट पाकिस्तान में छपे जाते हैं। बाजार में नकली करेंसी आने से मौजूद धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो बाजार में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है और माल एवं सेवाओं की भारी मांग उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त ऐसे नकली नोटों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है।

प्रधान संपादक - दयाराम दिव्य

शाहपुरा के विद्यालय में वाटर कूलर भेंट कर किया पुण्य कार्य



द मूवमेंट ऑफ इंडिया

सुरज वर्मा

शाहपुरा शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलिंजरी गेट में बच्छखेड़ा निवासी समाजसेवी राम कुंवार जी गौरा (पिता छीतर गौरा) द्वारा विद्यार्थियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था हेतु वाटर कूलर भेंट किया गया। कूलर के शुभारंभ के अवसर पर फल वितरण भी किया गया। इस अवसर पर उनके सुपुत्र केदार गौरा ने कहा कि बालक-

बालिकाओं को स्वच्छ व ठंडे जल की सुविधा उपलब्ध कराना एक पुण्य का कार्य है और समाज को ऐसे कार्यों में आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में संस्था प्रधान जयदीप सिंह बड़गुर्जर, ज्योति मूंदड़ा, बजरंग लाल आचार्य, पूर्णिमा व्यास एवं मौलाना मुमताज उपस्थित रहे। संस्था प्रधान बड़गुर्जर ने गौरा परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सहयोग से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बेहतर होंगे।

बालाजी गौवंश हेल्पलाइन की वार्षिक बैठक संपन्न

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

सुरज वर्मा

शाहपुरा के प्रसिद्ध खानियों के बालाजी मंदिर प्रांगण में बालाजी गौवंश हेल्पलाइन की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में शाहपुरा, भीलवाड़ा, केकड़ी और अजमेर जिले के बालाजी गौवंश हेल्पलाइन टीम के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। गौवंशों के हितार्थ चर्चा बैठक में गौवंशों के हितार्थ किए जाने वाले कार्यों के संबंध में



चर्चा हुई और गौ सेवा के संबंध में आने वाली समस्याओं के बारे में विचार विमर्श हुआ। कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव

साझा किए और गौवंशों की सेवा में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। बेहतरीन सेवा सम्मान

टीम द्वारा गोसेवा में बेहतरीन योगदान देने वाले गौसेवकों का दुपट्टा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया गया। भोजन प्रसादी का कार्यक्रम कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर गौवंशों की सेवा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

मेघवाल बने भीम सेना के सलूम्बर जिला प्रभारी

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

सुरज वर्मा

भीम सेना राजस्थान द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता विजेश मेघवाल को सलूम्बर जिला प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संगठन के संस्थापक एडवोकेट अनिल टिडुदिया के निर्देश पर प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश रायकवाल एमनिया पाड़ला की अनुशंसा पर प्रदेश संयोजक मोती मेघवाल ने



संगठन के उद्देश्यों एवं संविधान के प्रति उनकी निष्ठा को देखते

हुए की गई है। विजेश मेघवाल, निवासी सलूम्बर, लंबे समय से सामाजिक न्याय, समानता और संविधान संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति से संगठन को सलूम्बर क्षेत्र में नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ ही नई नियुक्तियों में गौरांग मीणा इटाली पाल को जिला उपाध्यक्ष, जितेंद्र वडेरा को झल्लारा ब्लॉक

उपाध्यक्ष, वालाराम मेघवाल भरदा ग्राम अध्यक्ष और दिनेश मेघवाल को भरदा ग्राम सचिव के पद पर नियुक्त किया। भीम सेना का उद्देश्य - सामाजिक न्याय, संविधान और राष्ट्रहित को समर्पित संगठन ने विश्वास जताया कि विजेश मेघवाल संगठन को मजबूती देंगे और बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे।

शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने वाला शिक्षक होगा नौकरी से बर्खास्त, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए निर्देश

भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के पंचायत शिक्षक का है मामला

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा जिले के पंचायत समिति मांडलगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोटरों का खेड़ा में पद स्थापित पंचायत शिक्षक मीठालाल मीणा को नौकरी से बर्खास्त

करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री के निजी सहायक ने बताया कि प्रसारित समाचार के अनुसार संज्ञान में प्रकरण आया था कि शिक्षक मीठालाल मीणा बालिका के साथ सदिग्ध अवस्था में अपने किराए के कमरे पर पकड़ा गया

था। जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी धुनाई कर दी। मामला संज्ञान में आते ही शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने उक्त शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए इसे सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री श्री दिलावर ने

कहा कि शिक्षक की गलत हरकत से पूरे विभाग की छवि धूमिल हुई है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिक्षक और शिक्षार्थी का रिश्ता पवित्र होना चाहिए। ताकि अभिभावक अपने बच्चों को बिना किसी डर और संकोच के स्कूल में पढ़ने भेज सकें।

आज राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या हुई है, सभी वर्गों ने की कड़ी निंदा।

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

हम राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं - क्या इस देश में नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है या नहीं? अगर नहीं है, तो स्पष्ट रूप से कहिए। अगर है, तो फिर शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण अनशन कर रहे नागरिकों को बलपूर्वक क्यों हटाया गया? आप नेता प्रशांत कुमार जायसवाल ने बताया कि डोल का बाढ़ आंदोलन को जयपुर शहर में कहीं भी विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई। मजबूर होकर आंदोलनकारी शहीद स्मारक पहुँचे - जो स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा घोषित आधिकारिक विरोध स्थल है। लेकिन आज दोपहर 4 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस ने धावा बोल दिया और वहाँ उपस्थित सभी नागरिकों को जबरन हटा दिया। इन्हें हटाना ही नहीं, बल्कि हिरासत



में लेना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। यह लोकतंत्र नहीं, दमन है। जायसवाल ने बताया कि आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें, जिनको लेकर आज अनशन का पहला दिन था (आंदोलन का 21वां दिन) - 1. डोल का बाढ़ क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाई जाए।

2. डोल का बाढ़ को बायोडायवर्सिटी पार्क घोषित करने के वैकल्पिक प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। 3. डोल का बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य रोका जाए जब तक सभी पक्षों की सहमति से समाधान न निकले। इस पर निगरानी रखने हेतु एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए। 4. माननीय मुख्यमंत्री से कम से

कम 10 मिनट का समय दिया जाए ताकि प्रत्यक्ष संवाद से समाधान की दिशा तय हो सके। इसमें जयपुर के सौ से अधिक नागरिक सहभागी थे, जिनमें से कई मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर से आते हैं। इसके बावजूद, पुलिस ने इस शांतिपूर्ण जन आंदोलन को बर्बरता से कुचल दिया - यह लोकतंत्र की खुली हत्या और तानाशाही है।

हर सुबह मौसम की मार!



मैं जलवायु परिवर्तन का मारा हूं। आप नहीं मानते? चलिए, मत मानिए। पर हर सुबह बीबीसी, सोएनएन, फ्रांस 24, एबीसी जैसी वैश्विक टीवी चैनलों पर दुनिया के (ताजा टेक्सास में बाढ़) जो फुटेज दिखते हैं, वे सभी के दिलो-दिमाग में सवाल पैदा करते होंगे कि यह हो क्या रहा है? न्यू मेक्सिको में बाढ़, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में भूस्खलन, यूरोप में 44 डिग्री की दोपहर, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, चीन में डूबती सड़कें हर फुटेज एक ही सवाल पैदा करता है, यह हो क्या रहा है? मेरा मानना है कि दुनिया के बाकी इलाकों की तुलना में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मानसून का उत्पात खबरों में भले दबा हो, लेकिन मार बहुत गहरी है। राजधानी दिल्ली की सड़कों के गड्ढों से लेकर गुजरात, हिमाचल में पुल टूटने, सड़कें बंद होने जैसी छोटी-छोटी खबरें भी यह आवश्यकता बतलाती हुई हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन-जलवायु परिवर्तन के लिए अब रक्षा मंत्रालय जैसी अहमियत वाला एक अलग मंत्रालय बनना चाहिए। पर आपदा को हम लोग क्यों कि न्यति मानते हैं, तो सोचना कैसे संभव? दृढ़ तंत्र में कोई संवेदना ही नहीं है। अमेरिका में जहां तहसीलनुमा काउंटी का मेयर भी आपदा पर सिसकता है, जिम्मेदारी लेता हुआ दिखता है, वहीं भारत में आपदा एक अवसर है, हर तरह का अवसर। दौरे, दिखावे और प्रेस मिलीज, फोटोशूट का अवसर, न कि जिम्मेदारी स्वीकारनेस सबक सीखने या चेतावनी देने का। इसी सप्ताह यूरोप, खासकर स्पेन की सड़कों के ऐसे चित्र दिखे, जिनमें 40 डिग्री की गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने हवा को उड़ा करने वाली मशीनें सड़कों के किनारे लगा रखी थीं। वही दोपहर में काम की छुट्टी भी घोषित ग थी। स्विट्जरलैंड में पहाड़ ढहने और घाटी के नीचे की बस्ती के बचाव के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली और वैज्ञानिक प्रबंधन विकसित हुआ हैं जिसके ग्लेशियर, पहाड़ टूटने से घाटी पूरी तरह मिट्टी से पट गई मगर एक आदमी नहीं मरा। जबकि भारत में? जर्जर पुल की रिपोर्ट भी फाइल में दबी रहती है और तब तक ट्रैफिक चलता रहता है, जब तक पुल बह न जाए। हालांकि टेक्सास की तबाही ने दिखा दिया है कि विज्ञान और मशीनरी की चुस्ती भी प्रकृति की प्रलय के आगे बेबस है। अमेरिका भी वैसा ही नुकसान झेलता दिख रहा है जैसा दुनिया के बाकी देश। मगर चूंकि अमेरिका वैश्विक मीडिया के फोकस में होता है, वहां की आपदा नजर आती है। जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में आपदाएं गुमनाम बनी रहती हैं। असल सच्चाई है कि प्रकृति की विनाशशीला का सबसे बड़ा केंद्रीय बिंदु दक्षिण एशिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार उपमहाद्वीप में ही प्रकृति का सर्वाधिक कहर बरपना है।

बेचारा विपक्ष, क्या रास्ता है!



बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी विपक्ष के पास रास्ता नहीं है? कैसी कमाल की बात है कि इन दिनों अदालतों के फैसले या सत्ताएं भी ऐसी होती हैं, जिससे दोनों पक्ष खुश हो जाएं। जैसे इन दिनों दुनिया भर में लड़इयां ऐसी होती हैं, जिनमें दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में बार दिन लड़ाई हुई तो दोनों देशों ने जीत का जश्न मनाया और जुलूस निकाले। उधर ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई तो दोनों देशों ने युद्धविराम के बाद जीत का दावा किया और विजय जुलूस निकाला। तीन साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे परत कर देने का दावा कर रहे हैं। और बिहार में मतदाता सूची पर हो रही लड़ाई पर गौर करें? सर्वोच्च अदालत ने फैसला देने की बजाय कुछ सवाल उठाए और चुनाव आयोग को सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल सही उठाए। यह पूछा कि नागरिकता प्रमाणित करना केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है तो आप क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं तो आपने इतना कम समय क्यों दिया? कम समय दिया तो आधार, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे सवाल सही थे लेकिन इनका जवाब मांगने और प्रक्रिया पर रोक लगाने की बजाय अदालत ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि वह अपना अभियान जारी रखे लेकिन आधार, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड को भी वैध दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करे। भला इसके बाद विपक्ष के पास क्या कोई रास्ता बचता है? विपक्षी पार्टियां बिहार में प्रदर्शन कर चुकी हैं। उन्होंने बिहार बंद भी कर लिया, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिला। उसके बाद न्यायिक रास्ता भी अपना लिया। सो, अब उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है कि वे इस प्रक्रिया में शामिल हों। विपक्षी पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताया। हालांकि वास्तविकता यह है कि इसमें उनकी कोई जीत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मौखिक सलाह से पहले ही बिहार में बृथ लेवल अधिकारियों ने नागरिकों से आधार कार्ड लेना शुरू कर दिया था। वे बिना आधार के भी मतगणना प्रप्रत्र स्वीकार कर रहे थे। उनको पता है कि इसके बाद का काम उनके हाथ में है। जनता के हाथ में प्रप्रत्र पहुंचा दिया और भाव हुआ प्रप्रत्र उनसे ले लिया। अब उसके बाद किसका नाम अपडेट किया जाना है और किसका नाम कट जाना है यह तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के हाथ में है। विपक्ष अब इसमें कुछ नहीं कर सकता है।

लोकतंत्र में लाठी का राज!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाठी भांज रहे हैं। उनको परवाह नहीं है कि लाठी अपने दोस्तों को लग रही है या दुश्मनों को। उनके हाथ में उस्तरा है तो वे उसे जैसे तैसे चला रहे हैं। यूरोप के देश हैरान परेशान हैं तो दक्षिण कोरिया और जापान जैसे दोस्त भी परेशान हैं। ट्रंप ने उनके ऊपर भी भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। लेकिन यह सिर्फ अमेरिका की परिघटना नहीं है। व्लादिमीर पुतिन के पास भी लाठी है तभी तो उन्होंने एक दिन कहा कि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले इलाकों पर उनका अधिकार है और यूक्रेन पर हमला कर दिया। चीन के शी जिन्पिंग को भी अपनी लाठी का बड़ा घमंड है तो वे कभी ताइवान को धमकाते हैं तो कभी संप्रभु भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के शहरों, कस्बों के नाम बदलने लग जाते हैं। यह कहानी भारत में भी दोहराई जा रही है। हालांकि भारत किसी दूसरे देश के खिलाफ लाठी नहीं भांज रहा है, बल्कि वह अपने ही नागरिकों पर, किसी न किसी रूप में सत्ता या शक्ति की लाठी चला रहा है। ग्यारह वर्षों का कमाल ही हा जो 'नोटबंदी' से 'वोटबंदी' तक लाठीराज भारत की पहचान है। एक दिन अचानक जैसे नोट बंद किए गए थे उसी तरह एक दिन अचानक चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के हर नागरिक को अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। ऐसे ही कहीं आकाशवाणी हुई कि बहुत जल्दी इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले शर्मिदा होंगे और उसके बाद एक फरमान आया कि अमुक राज में पहली कक्षा के बच्चों को हिंदी पढ़नी होगी। इसके विरोध में कुछ लोग लाठी लेकर सड़क पर उतर गए। चुन चुन कर गैर मराठी लोगों से मराठी बुलवाने का उत्सव शुरू हुआ और नहीं बोलने वालों पर लाटियां चलने लगीं। इसी तरह एक दिन अचानक कुछ लोग लाठी लेकर सड़कों पर उठे और दुकानदारों की पहचान जानेंगे लगे। उनके यूपीआई लिंक पर जाकर चेक करने लगे कि वह हिंदू है या मुस्लिम। उससे उसका नाम दुकान पर लगाते, न लगाने या बंद करके भाग जाने को कहा जाने लगा। दिल्ली में नगर निगम ने कहा है कि निगम के किसी कानून में



नहीं लिखा है कि कांवड़ के रास्ते में पड़ने वाली मांस की दुकानों को बंद किया जाए। लेकिन जिनके हाथ में लाठी है वे लाठी लेकर घूम रहे हैं और मांस की दुकानें बंद करा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि फिल्म का नाम 'जानकी' नहीं होना चाहिए। फिर वह उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दे रहा है और फिल्म के नाम को लेकर घमासान लड़ाई होती है। किसी को लगता है कि कन्हैयालाल दर्जी की हत्या के ऊपर 'उदयपुर फाइल्स' नाम से फिल्म नहीं बननी चाहिए तो वह उस विषय पर लड़ाई शुरू हो जाती है और अदालत उस पर रोक भी लगा देती है। एक तरफ चुनाव आयोग बिहार के लोगों से कहता है कि आप अपनी नागरिकता प्रमाणित करें। लोग अपनी नागरिकता का सबूत दे। दूसरी ओर एक अदालत कहती है कि कोई व्यक्ति दुर्घटना में मारा गया है और उसके परिजन बीमा की राशि क्लेम करने गए हैं तो परिवार के लोग साबित करें की दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति अपनी गलती या लापरवाही से तो नहीं मरा है! ऐसे ही एक दिन सरकार कहती है कि अमुक यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा और वह बंद हो जाता है या अमुक एक्स अकाउंट बंद होना

वोटर लिस्ट की कटाई-छंटाई तो होगी!

यों बिहार में विपक्षी पार्टियों ने बृथ लेवल एक्ट्रेस नियुक्त किए हैं। पर वे आम लोगों को दस्तावेज जुटवाने में ही मदद कर सकते हैं। उनके दस्तावेज बृथ लेवल अधिकारियों के पास जमा करावाएं और पुनिश्चित करें कि उनका नाम अपडेट हो। एक अगस्त से मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियां ली जाएंगी। यानी किसी का नाम कट गया है तो उसे जुड़वाने का मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि एक अगस्त से फिर नोटबंदी वाली कहानी दोहराई जाने वाली है। अभी जित्त तक से लोगों से फॉर्म लिए गए हैं और बिना दस्तावेजों के भी फॉर्म स्वीकार किए गए हैं। उससे लग रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटेंगे और जिनके नाम कटेंगे उनको हर जिला या प्रखंड के चुनाव कार्यालय में लाइन लगा कर, अपने दस्तावेज लेकर खड़ा होना होगा। सावन, भादो का महीना होगा। बारिश हो रही होगी। बारिश से या नेपाल के पानी से आधा बिहार बाढ़ में डूबा होगा लेकिन बिहार के लोगों की न्यति है कि वोट डालना है तो दस्तावेज लेकर चुनाव कार्यालय के



बाहर खड़े रहें। अगर कोई खुशकिस्मत होगा तो आपत्ति का निपटारा हो जाएगा और मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाएगा। देश के विपक्ष की ऐसी असहायता केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में है। उसे कहीं से कोई राहत नहीं है। भाजपा का एकमात्र लक्ष्य किसी तरह से चुनाव जीतने का है। चुनाव आयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ न कुछ ऐसे काम जरूर कर रहा है, जिसका लाभ सत्तारूढ़ दल को हो रहा है। तभी विपक्षी पार्टियों की बेचनी समझ

आती है। राहुल गांधी ने तो सीधे तौर पर मैच फिक्स होने की बात कही है। बिहार में मतगणना पुनरीक्षण शुरू करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया है कि इसके बाद परिचम बंगाल और असम की बारी है। तभी सप्ता बनर्जी की पार्टी को सांसद महुआ मोइत्रा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। विपक्षी पार्टियों ने पहले चुनाव आयोग के आगे गृहार लगाईं। कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वे सड़कों पर उठे लेकिन फिर भी सरकार या चुनाव आयोग पर कोई कर्क नहीं पड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्ष की 10 पार्टियों ने याचिका दायर की थी। देश के सबसे अच्छे संवैधानिक जानकार वकील उनकी तरफ से लड़े लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद भी 2024 के जिस मतदाता सूची पर लोकसभा चुनाव हुआ था उसके आधार पर विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नई मतदाता सूची के आधार पर होगा, जिसे अब चुनाव आयोग बनवा रहा है। पर विपक्ष को चुनाव तो लड़ना है।

इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग मशीन के प्रति अपनी इस शिकायत के बावजूद कि मशीन हैक हो जाती है और उससे मतदान को प्रभावित किया जाता है। कहीं विपक्ष को लगता है कि फर्जी नाम जोड़े गए हैं तो कहीं लगता है कि जायज नाम कटे गए हैं। उनको चुनाव आयोग से समस्या है, जो सत्तापक्ष के नेताओं पर कठवाई नहीं करता है। मतदान के 48 घंटे बाद तब मतदान का आंकड़ा बढ़ाता रहता है और बाद में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं करता है। विपक्ष को सरकार से शिकायत है कि वह धन बत या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनकी पार्टियों को कमजोर करती है। इन तमाम शिकायतों के बावजूद विपक्ष को चुनाव लड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वे चुनाव का बहिष्कार कर दें। क्या इसका यह मतलब है कि विपक्षी पार्टियों को अपने ही आरोपों पर संदेह है? दरअसल उनको यह भी लगता है कि वे चुनाव जीत भी सकते हैं, जैसे झारखंड में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में जीते थे।

हर सुबह ट्रंप के दिवत का गड्ढा!

समय का तमाशा है, जो सुबह की चाय से पहले, दुनिया में एक और रस्म जुड़ी है कि आज ट्रंप क्या बोलें? हर सुबह एक ट्विट आता है, और शेयर बाजार से लेकर सरकारों की नीतियों तक, सब हिलने लगती हैं। देशों के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक, कारोबारियों, आर्थिकी का दिन ट्रंप के ट्विट से ही शुरू होता होगा। सबका काम ट्रंप की उंगली के इशारे पर रुकता और चलता है। एक किस्म की वैश्विक बेबसी, और वह भी सिर्फ 280 अक्षरों में! हां, भारत में अब दलाल स्ट्रीट के कारोबारी भी पूछते हैं, ट्रंप भारत की बांह किसनी मरोड़ेंगा? व्यापार करार हो रहा है या भारत हिम्मत दिखा रहा है? एक जमाने में कहा जाता था, अमेरिका छींकता है तो दुनिया को जुकाम होता है। अब अमेरिका का राजा ट्विट करता है, और पूरी दुनिया चौंक जाती है। पर यह सिर्फ ट्रंप की बात नहीं। मौजूदा समय का यह वह आईना है, जहां जलवायु परिवर्तन से लेकर राजनीतिक नेतृत्व तक, हर तरफ एक बेहदगी और भय की मिलीजुली हवा है। दुनिया के साढ़े सात अरब लोग हर दिन किसी न किसी झटके, गड्ढे, तनाव या हंगामे से टकरा रहे हैं। 'नॉर्मल' अब जैसे कोई बीती कहानी हो गई हो। सोचें, डोनाल्ड ट्रंप और अपने नरेंद्र मोदी पर। सप्ताह की शुरुआत इस खबर से हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित



किया जाएगा, पहले पाकिस्तान, अब इजराइल भी उन्हें अमन का फरिश्ता करार दे कर उनका प्रस्तावक होगा। इधर भारत में सोशल मीडिया पर उत्सव था कि घाना सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' का तमगा दिया। उन्हें घाना सहित नामीबिया, त्रिनिदाद और टोबैगो आदि देशों से एक के बाद एक 26 देशों से 'सर्वोच्च नागरिक सम्मान' मिले हैं। मतलब कि, वे दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसका अर्थ यह भी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी दो-चार सम्मानों वाले प्रधानमंत्री थे, जबकि भारत के असली, अकेले विश्वगुरु प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी! अब जरा पूछें कि मई

2025 को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो क्या इन 26 देशों में से किसी देश ने भारत के पक्ष में, पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शब्द बोला? एक भी देश, सिवाय इजराइल के, भारत के साथ खड़ा नहीं था। महाशक्ति देशों का तो खैर सवाल ही नहीं। न ही भारत की पीड़ा के समय में किसी ने पाकिस्तान की निंदा या सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की पहल की। भारत की कूटनीति में इन 26 देशों में किसने, कितनों ने भारत के सुर

और भारत में क्या सुर्खियां हैं? देखों, देखो मोदीजी को उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता के लिए घाना, नामीबिया, फिजी, ब्राजील, बहरैन, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। पर यह भी सोचें कि इनमें क्या कोई पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़ा था? यह विषयांतर नहीं, मौजूदा समय के इस असल मुद्दे की परत है कि वैश्विक राजनीति में जो शोरगुल दिखता है, वह अंदर से कितना खोखला हो चला है। ट्रंप महीनों से देशों को धमका रहे हैं, व्यापार करार के लिए झुका रहे हैं। बावजूद इसके यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सब देशजार में हैं कि ये ड्रामा कहाँ जाकर थमेगा। ट्रंप द्वारा दुनिया को धमकाते-धमकाते कई महीने हो गए हैं। दो-चार देशों को छोड़ कर उनकी शर्तों के अनुसार व्यापारिक करार करने के लिए देश तैयार नहीं हो रहे हैं। यूरोपीय संघ से लेकर आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सभी तमाशा देख रहे हैं कि होता क्या है? जैसे मौसम, जलवायु परिवर्तन की आग दाढ़ा और उनका प्रभाव है वैसे ही ट्रंप के ट्विट बड़बोलेपन का ढोल है। उनका नोबेल शांति पुरस्कार या भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रों के वैश्विक सम्मान की बात, सभी गुंजते ढोल की तरह हैं, बजते बहुत हैं, लेकिन भीतर से खाली।

बेमुश्कल निर्ममता को छू रही पक्षधरता!

क्या आप देश के तकरीबन 400 समाचार चैनलों में से दो-चार भी ऐसे बना सकते हैं, जो आजकल सरकार के निर्णयों और नीतियों में खामियों को उजागर करना तो दूर, उन की तरफ इशारा करने का काम भी करते हों? एक लाख के आसपास अखबारों-पत्रिकाओं में से क्या सी-पचास भी ऐसे हैं, जो केंद्रीय, प्रादेशिक या जिला स्तरीय शासन-प्रशासन के कामकाज की समीक्षात्मक रपटें प्रकाशित करते हों? पत्रकारिता के दो अलग-अलग कंगूर हैं। एक है, जिस ने अपनी दीवार पर 'मुख्यधारा-मीडिया' का बोर्ड अपने आप टांग कर खुद को हम पर थोप दिया है। दूसरा है बे-धारा मीडिया। इसे आप जो चाहें, कह लें - सोशल मीडिया कहें, एंटी-सोशल मीडिया कहें। वह जैसा भी है, अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से दर्ज करा रहा है। इन में से एक कंगूर के सामने तो आने वाले समय में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती उस के सामने होती है, जो सचेत हो; जो सही के साथ खड़ा हो; और, जिसे लोकलजाज का कुछ लिहाज हो। मगर जो इस्कादुक्का परदे-पत्रे अपने कर्तव्यबोध से थोड़ा-बहुत बंधे दीखते भी थे, उन्होंने भी इन ग्यारह बरस में जल-समाधि ले ली है। मुख्यधारा-मीडिया का पूरा समंदर करंपोरेट-बंदरगाहों के हवाले हो गया है। इस निगमीकृत व्यवस्था ने सुबह के पत्रों पर और शाम के परदों पर बजने वाली आत्मी-धुनों को समरूप बना दिया है। सो, 'तुम्हारी भी जय-जय, हमारी भी जय-जय' वाले इस माहौल में कैसी चुनौती? किस से चुनौती? मोसरे भाइयों को एक-दूसरे से काहे की चुनौती? जो कुछ चुनौती है, सोशल मीडिया के सिर्फ एक हिस्से के सामने है। घनघोर वैचारिक धुवीकरण के इस मारकाट भर दशक ने सोशल मीडिया को दो-फाड़ कर रखा है और दोनों ही तरफ के आग कतर्थाबन बरबक लगी हुई। मुख्यधारा-मीडिया का और भी नंग-भड़ंग घुछल्ला बन कर, हूकूमत-उड़ूली करते लग रहे तबके पर गालियों के गोले दाह रहे सोशल मीडिया के हिस्से को कहीं से कोई चुनौती न तो है, न तब तक होगी, जब तक जिल्ले-सुब्बानी का वरदस्तेत मौजूद है। मुख्यधारा-मीडिया की तरह उस के भी भय-दिव्य पालन-पोषण का जिम्मा, उठाने वालों ने, उठा रखा है। इंद्रप्रसा की संरक्षण-छतरी के सागे में बैठ कर वह आराम से मत्स्य-आखेट का आनंद ले रहा है। उस दूसरे हिस्से की यह जरूर

शुरू से पथरीली है, जो बेतरह भड़काऊ और भद्दी गालियों से खुद और अपने परिवारजन की चर्दारी को तार-तार करवा कर भी अनुचित से असहमति की धुन बजाते रहते में मशगूल है। उसे आने वाले समय में चुनौतियां के और भी दुरुह पहाड़ पार करने होंगे। चुनौती की चौकियां लगातार चप-नए सशस्त्रों से लैस होती जाएंगी और सोशल मीडिया की पैदल सेना दिनोंदिन और भी निरह्वी। यह संघर्ष एक-बनाम-एक का तो कभी था ही नहीं। हमेशा से डेढ़-बनाम-आधे का था। अगर सामाजिक शक्तियां इसी तरह उनींदी रहें तो कहीं वह पौने दो-बनाम-चौथाई का ही न रह जाए? ठीक है कि आज के मीडिया से बह रही आबोहवा जरा ज्यादा ही हताशा और निराशा पैदा करने वाली है, मगर इस का मतलब यह नहीं है कि मीडिया की पक्षधरता का मौसम इस से पहले कभी था ही नहीं। वह हमेशा था। पत्रकारिता वैचारिक पक्षधरता से मुक्त रह भी नहीं सकती है। मगर ऐसा समय इस से पहले कभी नहीं था कि पत्रकारिता ने अपने संयम और संतुलन को पूरी तरह ठेंग पर दब लिया हो। आज तो पत्रकारीय पक्षधरता की धार कसाईपन की बेमुश्कल निर्ममता को छू रही है। पहले भी मीडिया में व्यवस्था-नर्मथक और व्यवस्था-विरोधी खेमे हुआ करते थे। मगर सत्ता-समर्थक मीडिया का आकार बहुत छोटा होता था और वह इतना अंधेधनक भी नहीं होता था। व्यवस्था-विरोधी मीडिया को पटार रखने और अपने हिस्साब से चलाने की कोशिशें सरकारें पहले भी करती थीं। लेकिन यह एक दशक हूकूमत की तरफ से पटा-पटाई के प्रयासों में नहीं, डंडे और एमन के गुप्त हथियारों के निर्लज इस्तेमाल के जरिए मीडिया को घुटनों पर लाने का रहा है। यह दशक सत्तासीनों द्वारा अपने सहचर पूंजीपतियों के माध्यम से मीडिया मंचों को हड़ल लेने का रहा है। इस पूरे दशक में हम ने मीडिया को जनता के सजग पहरा से सरकार की पलटन में तब्दील होते देखा है।



से प्रशासन के विभिन्न अंगों में भी मौजूद है। वह अर्थतंत्र के संसार को चलाने वालों में भी उतनी ही गहराई से घुसी हुई है। ऐसे हालात में क्या भारतीय मीडिया अपनी असहाय स्थिति से सचमुच कभी उबर पाएगा? किसी नई उदारवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होने तक मीडिया के मौजूदा चरित्र में कोई सकारात्मक परिवर्तन होने की उम्मीद पालना इसलिए निरर्थक है कि पिछले दस-ग्यारह साल से जिस शेर की सवारी हमारा मीडिया कर रहा है, उस पर से नीचे उतरने का नतीजा वह बखूबी जानता है। सो, जाने-अनजाने, खुशी-खुशी या मजबूरी में, जो खाल हमारे टीवी सूत्रधारों और अखबारों संपादकों ने ओढ़ ली है, इच्छा हो तो भी, उस से मुक्ति उन के लिए मुमकिन नहीं है। अब उन्हें इसी हाल में जीना है और अपने हुकूमरानों से वकादारी का इजहार हर रोज और भी जोर-जोर से करते रहना है। क्या आप देश के तकरीबन 400 समाचार चैनलों में से दो-चार भी ऐसे बता सकते हैं, जो आजकल सरकार के निर्णयों और नीतियों में खामियों को उजागर करना तो दूर, उन की तरफ इशारा करने का काम भी करते हों? एक लाख के आसपास अखबारों-पत्रिकाओं में से क्या सी-पचास भी ऐसे हैं, जो केंद्रीय, प्रादेशिक या जिला स्तरीय शासन-प्रशासन के कामकाज की समीक्षात्मक रपटें प्रकाशित करते हों? मुख्यधारा-मीडिया

आज के मीडिया के सबसे सब से बड़ी चुनौती इस पलटनवाद के विस्तार का सामना करने की है। मीडिया में पलटनवाद को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति महज राजनीतिकों में ही नहीं है। वह उतनी ही बीहड़ता

के डिजिटल चैनलों के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, मगर सामयिक सामाजिक-राजनीतिक मसलों पर अपनी बात कहने वाले जो पांच-सात हजार छोटे-मध्यम चैनल यूट्यूब पर मौजूद हैं, क्या उन में से बीस-तीस प्रतिशत से ज्यादा को आप ने जनें-मुखी मुद्रा अपनाते देखा-सुना है? मगर इस अनंतकार परदे रंगिस्तान के बीच-बीच में कुछ नखलिस्तान कहीं तो निश्चित ही होंगे। इसलिए कोहरे में डूबी दिशाओं के इस दौर में भी इतना आश्चर्य में जरूर हूँ कि जिस तरह मुख्यधारा-मीडिया को आज के सत्तासीनों ने पूरी तरह लील लिया है, वैकल्पिक मीडिया के मंचों को वे उस तरह कभी पूर्णतः गटक नहीं पाएंगे। अपनी टूटी तलवारों, अपने घायल अश्वों और लूंपजुंज होती अपनी मांसपेशियों के बावजूद वैकल्पिक मंचों से शंखों का नाद आप को हर रोज भोर में भी जगाता रहेगा और गोधूलि बेला में भी खबरदार करता रहेगा। उम्मीद की यह मद्दम-सी ली भी भावी धूसर आसमान के लिए इसलिए काफी है कि चिंगारि अगर जिंदा रहे तो उसके ऊपर जमी राख उड़ाने के लिए तो एक फूंक ही बहुत है। इस फूंक को सरकार क्यों दमदार बनाना चाहेगी? इस फूंक में तो समाज को प्राण फूंकने होंगे। जब तक भारतीय समाज की सामूहिक चेतना इस अहसास के साथ झटके से नहीं जागती कि अब देर करने का वक़्त गया, कि और देर हुई तो गैरिया-दशा की पहुंच चुकी पत्रकारिता के डोडों की तरह विलुप्त हो जाने की बदनसीबी को थामना असंभव हो जाएगा, तब तक बहुत आस मत लगाइए। क्योंकि सोशल मीडिया को अपनी जाजम मुहैया कराने वाले भी कौन-से सामाजिक सरंकारों के रखवाले हैं? वे यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सऐप जैसे उपादान क्या परोपकार के लिए संचालित कर रहे हैं? इन उपादानों पर दुनिया के हर देश की सरकारों के नियमन अपनी-अपनी बहरतों के हिसाब से कसते-ढीले होते हैं। भारत भी इस प्रक्रिया पर सामदमाी अमल करने में कोई फिसड्डी तो साबित हो नहीं रहा है! उस दिन की कल्पना करिए, जब निश्चिति सम्राट से किसी भी तरह की असहमति को सोशल मीडिया के सभी संवाहक मंचों की टुन से उठा कर कपड़ों लतों समेत बाहर फेंक दिया जाए। भारत भाग्यशाली होगा तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, वरना 'जाहि विधि राखे राम'।

शुभमन गिल ने दिखाई जैक क्रॉउली को उंगली... अब सपोर्ट में उतरा ये अंग्रेज, कहा-यही होना चाहिए



एजेंसी लंदन

लॉर्ड्स मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन खूब ड्रामा हुआ। शनिवार को खेल खत्म होने के आखिरी पलों में तनाव बढ़ गया। दिन की रोशनी कम हो रही थी और खिलाड़ी जोश में थे। भारतीय टीम इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना चाहती थी। जसप्रीत बुमराह को गेंद दी गई और उन्होंने शुरुआत में ही विकेट लेने की कोशिश की। जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के खिलाड़ी जैक क्रॉउली के बीच बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि मैदान पर गर्मागर्मी हो गई। भारत के कप्तान शुभमन गिल भी इसमें शामिल हो गए। केविन पीटरसन जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने इस घटना पर अलग-अलग राय दी है। उन्होंने खेल में इस तरह के तनाव को अच्छा बताया है। इसलिए आने वाले दिनों में और भी रोमांच देखने को मिल सकता है। शनिवार को लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बहुत गर्मागर्मी थी। दिन का खेल खत्म होने वाला था और भारतीय टीम पूरी तरह

से तैयार थी। वे इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्रॉउली और बेन डकेट को परेशान करना चाहते थे। जसप्रीत बुमराह को गेंद दी गई। उन्हें जल्दी विकेट लेने का काम सौंपा गया। बुमराह ने क्रॉउली को अपनी तेज गेंदबाजी और अलग-अलग तरह की गेंदों से परेशान किया। लेकिन अपनी दूसरी गेंद के बाद, बुमराह थोड़े गुस्से में दिखे। उन्हें लगा कि क्रॉउली जानबूझकर खेल को धीमा कर रहे हैं। जब बुमराह गेंद फेंकने के लिए दौड़े, तो क्रॉउली क्रीज से हट गए। इससे भारतीय खिलाड़ी और भी नाराज हो गए। स्लिप में खड़े कप्तान शुभमन गिल ने क्रॉउली को कुछ कहा। फिर उनके बाकी साथी भी इसमें शामिल हो गए। ओवर की पांचवीं गेंद पर क्रॉउली के हाथ में चोट लगी। उन्होंने तुरंत फिजियो को बुलाया और दस्ताना निकालकर देखने लगे। इस पर भारतीय खिलाड़ियों ने ताली बजाकर मजाक उड़ाया। गिल तो क्रॉउली की तरफ दौड़ते हुए पवेलियन की ओर इशारा करने लगे। क्रॉउली और भारतीय कप्तान के बीच कुछ बातें हुईं। बेन डकेट ने बीच में आकर गिल से बहस की, जिसके बाद खेल फिर से शुरू हुआ।

कंधे टकराकर फिर चिल्लाए मोहम्मद सिराज, अंपायर से मिल गई वॉर्निंग, बेन डकेट के विकेट पर भयंकर बवाल!

एजेंसी लंदन

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच के चौथे दिन मोहम्मद सिराज ने बेन डकेट को आउट कर सनसनी मचा दी। बेन डकेट ने सिराज की तेज तर्रार गेंद पर पारी के छठे ओवर में मिड ऑन की दिशा में एक कड़क शॉट लगाया, लेकिन वहां तैनात जसप्रीत बुमराह ने बड़ी ही चपलता से कैच लेकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। बुमराह ने जैसे ही बेन डकेट का कैच पकड़ा मोहम्मद सिराज का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इस विकेट के साथ ही मोहम्मद सिराज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। जश्न मनाने के दौरान के उनका कंधा बेन डकेट से टकराया और जिस तरह से उनका एक्सप्रेसशन बाहर आया अंपायर ने भी देखकर भारतीय



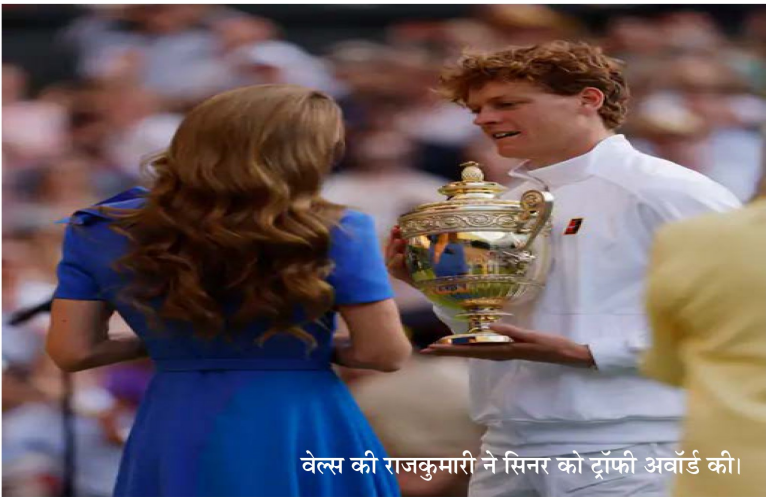
गेंदबाज को एक तरह से वॉर्निंग दे डाली, लेकिन सिराज के इस प्रतिक्रिया के साथ साफ पता चल गया कि लॉर्ड्स टेस्ट में अब दोनों टीमों के बीच एक अलग तरह का रोमांच देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत खेल के तीसरे दिन की समाप्ति के दौरान हुआ था।

इटली के जैनिंक सिनर ने जीता विम्बलडन, पिछले 2 टाइटल जीतने वाले अल्काराज को हराया



एजेंसी लंदन

वर्ल्ड नंबर-1 जैनिंक सिनर ने विम्बलडन के मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर ने पहली बार यह टाइटल जीता है। वे विम्बलडन चैम्पियनशिप का मेंस सिंगल्स टाइटल जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर कोर्ट में इटली के सिनर ने रविवार रात को 3 घंटे 4 मिनट चले मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ सिनर ने अल्काराज से 5 हफ्ते पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया है। 8 जून 2025 को अल्काराज ने सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। सिनर से लगातार 5 जीत के बाद हारे अल्काराज विम्बलडन के पिछले 2 टाइटल जीतने वाले अल्काराज अपने इटैलियन प्रतिद्वंद्वी सिनर के खिलाफ 5 मैच बाद हारे हैं। अल्काराज ने 3 घंटे 4 मिनट चले इस मैच का पहला सेट 6-4 से जीता और मैच में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। यहां से इटली के सिनर ने लगातार तीन सेट 6-4, 6-4, 6-4 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इगा स्वातेक ने जीता विमेंस सिंगल्स का खिताब एक दिन पहले शनिवार, 12 जुलाई को पोलैंड की इगा स्वातेक ने विंबलडन के विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता था। उन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा अर्निस्मोवा को सीधे सेटों में हराया। पहले पूरी खबर पोलैंड की इगा स्वातेक ने छठा ग्रैंड स्लैम जीता। वे 4 बार फ्रेंच ओपन और 1 बार US ओपन जीत चुकी हैं। उन्होंने पहली बार विंबलडन जीता। विम्बलडन टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 148 साल पहले 1877 में हुई थी। विम्बलडन इकलौता ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन कोई नेशनल टेनिस एसोसिएशन नहीं करता है। इसका आयोजन ऑल इंग्लैंड क्लब करता है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स इस क्लब की मालकिन रहती है। इस समय कैथरीन एलिजाबेथ मिडिलटन इसकी मालकिन हैं। विम्बलडन साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इसे टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम में सबसे प्रतिष्ठित भी कहा जाता है। टेनिस के कैलेंडर इयर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसकी शुरुआत जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। मई और जून में फ्रेंच ओपन होता है। जुलाई में विम्बलडन और अगस्त-सितंबर में US ओपन होता है। US ओपन साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है।



वेल्स की राजकुमारी ने सिनर को ट्रॉफी अर्वाड की।

त्यापार

अगले हफ्ते 3 आईपीओ खुलेंगे, ग्रे मार्केट में लगाई हुई है 'आग', निवेश के लिए पैसा रखें तैयार

एजेंसी नई दिल्ली

शेयर बाजार में आईपीओ का मौसम फिर से आने वाला है। 14 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में तीन नए आईपीओ खुलने वाले हैं। ये आईपीओ मेन बोर्ड और एसायर्स सेगमेंट में आएंगे। इन आईपीओ के जरिए कंपनियां कुल मिलाकर 3600 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने की तैयारी में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फार्मा कंपनी एंथेम बायोसाइंसेज (Anthem Biosciences) के आईपीओ की है। इसके अलावा SME सेक्टर की दो कंपनियां स्पनवेब नॉनवोवन लिमिटेड (Spunweb Nonwoven) और मोनिका एल्कोबेव (Monika Alcobev) भी आईपीओ लेकर आ रही हैं। इनमें से दो आईपीओ को ग्रे मार्केट में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पिछले हफ्ते Cryogenic OGS और GLEN Industries जैसे एसायर्स आईपीओ को निवेशकों ने खूब पसंद किया था। खासकर, रिटेल निवेशकों और HNI ने इनमें बड़-चढ़कर हिस्सा लिया था। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और ओवरसब्सक्रिप्शन के ट्रेंड को देखते हुए बाजार में काफी उत्साह है। लोगों को खास सेक्टर और सही कीमत वाले आईपीओ में



ज्यादा दिलचस्पी है। नए आईपीओ के अलावा अगले हफ्ते Travel Food Services समेत 7 कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट होने की भी उम्मीद है। अगर आप इन आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो पैसा तैयार रखें। यह मेन बोर्ड का आईपीओ है। बेंगलुरु की फार्मा कंपनी Anthem Biosciences 14 जुलाई को अपना आईपीओ खोलेगी। यह 16 जुलाई को बंद हो जाएगा। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसका मतलब है कि कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि मौजूदा शेयरधारक ही अपने शेयर बेचेंगे। कंपनी का लक्ष्य 540-570 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में 3,395 करोड़ रुपये जुटाना है। यह कंपनी

कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज (CRAMS) में माहिर है। CRAMS का मतलब है कि ये कंपनी दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च और दवा बनाने का काम करती है। इस कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे। लिस्टिंग 21 जुलाई को हो सकती है। इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में अच्छा रिसर्पोन्स मिल रहा है। 13 जुलाई को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) 100 रुपये था। इस जीएमपी के साथ यह आईपीओ 17.54% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है। एसायर्स सेक्टर में का यह आईपीओ भी 14 जुलाई को खुलेगा और 16 जुलाई को बंद होगा। यह कंपनी टेक्निकल टेक्स्टाइल बनाती है। कंपनी का लक्ष्य 90-96 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में 60.98 करोड़ रुपये जुटाना है। Vivro Financial इस आईपीओ के लिए लीड मैनेजर है। इस कंपनी के शेयर NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। इसकी भी लिस्टिंग 21 जुलाई को हो सकती है। यह कंपनी नॉनवोवन फैब्रिक बनाती है। इसका इस्तेमाल हाइजीन, एग्रीकल्चर और पैकेजिंग में होता है। सरटेनेबल मटेरियल की बढ़ती मांग की वजह से इस सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है।

एजेंसी नई दिल्ली

हमारे देश में जहां क्रिप्टोकॉरेंसी (Cryptocurrency) अभी भी चलन में नहीं है, वहीं दुबई में यह धमाल मचा रही है। लोग इसका इस्तेमाल फ्लाइट की टिकट बुक करने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक में कर रहे हैं। इस समय दुबई में क्रिप्टोकॉरेंसी खास जगह बना रही है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) टैक्स में छूट और निवेशकों के लिए अच्छे माहौल के कारण क्रिप्टो का केंद्र बन रहा है। दुबई में हाल ही में दो बड़े फैसले हुए हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस (Emirates Airlines) ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अब फ्लाइट की टिकट क्रिप्टो से बुक हो सकेंगी। दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) ने भी एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। इससे प्रॉपर्टी के सोदे ब्लॉकचेन तकनीक से हो सकेंगे। ये सब एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। साल 2025 की शुरुआत में क्रिप्टो बाजार 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का हो गया। लोग अब रोजमर्रा के कार्यों में भी क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबई सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इस मांग को



पूरा कर रही हैं। क्या 500 रुपये का नोट भी होने वाला है बंद? लोगों में पैदा हुआ कंप्यूजन, जाने वायरल मैसेज की सच्चाई दुबई में कुछ खास क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल होती हैं। इनमें बिटकॉइन (BTC), इथेरियम (ETH), टैथर (USDT) और यूएसडी डॉलर (USDC) प्रमुख हैं। यूएई में क्रिप्टो रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब है कि क्रिप्टो को बेचने, लगाने या माइनिंग करने से होने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं है। यह निवेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है। दुबई स्मार्ट सिटी बनना चाहता है। यहां ब्लॉकचेन (Blockchain)

को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए निवेश के नजारे से क्रिप्टो के लिए यहां अच्छा माहौल है। क्रिप्टो से दुनिया भर के निवेशक यूएई की अर्थव्यवस्था में आसानी से हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें बैंक और करेंसी बदलने का झंझट नहीं होता। 9 जुलाई 2025 को एमिरेट्स ने एक बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया। अब एमिरेट्स की टिकटें क्रिप्टो से खरीदी जा सकेंगी। यह सिस्टम अगले साल शुरू हो जाएगा। ग्राहक बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टोकॉरेंसी से टिकट खरीद पाएंगे। म्यामांर में उल्फा बैंक पर किसने किया ड्रोन अटैक? आर्मी ने दिया दो दूक जवाब शेख अहमद बिन सईद अल मक्तूम की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। एमिरेट्स का कहना है कि वह युवा और तकनीक पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर यह कदम उठा रही है। एमिरेट्स के डिप्टी प्रेसिडेंट अदनान काजिम ने कहा कि इससे ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। साथ ही यह पेंमेंट के नए तरीकों को अपनाने की दिशा में भी एक कदम है।



क्या 500 रुपये का नोट भी होने वाला है बंद ? लोगों में पैदा हुआ कंप्यूजन, वायरल मैसेज की सच्चाई

एजेंसी नई दिल्ली

क्या रिजर्व बैंक 2000 के बाद अब 500 रुपये का भी नोट बंद करने जा रहा है? दरअसल, वॉट्सएप पर एक मैसेज तेजी से फैल रहा है। इसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे एटीएम से 500 रुपये के नोट डालना धीरे-धीरे बंद कर दें। मैसेज कहा गया है कि मार्च 2026 तक एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलने लगना पूरी तरह बंद हो जाएगा। मैसेज में लिखा है, 'रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 30 सितंबर 2025 तक एटीएम से 500 के नोट देना बंद कर दें। लक्ष्य है कि 75% बैंकों के एटीएम और

फिर 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम से 500 के नोट बंद हो जाएं। आगे ATM से केवल 200 और 100 के नोट ही निकलेंगे। इसलिए अपने पास रखे 500 के नोटों को अभी से खर्च करना शुरू कर दें।' पीआईबी फैक्ट चेक ने इस मैसेज को पूरी तरह से झूठा बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है। इसमें लिखा है कि रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है और 500 रुपये के नोट अभी भी लॉगल टेंडर हैं। इसका मतलब है कि 500 रुपये के नोट अभी भी कानूनी रूप से मान्य हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीआईबी ने लोगों को ऐसी गलत सूचनाओं से बचने की सलाह दी है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने लोगों से

कहा है कि किसी भी खबर की सच्चाई जानने के लिए सरकारी वेबसाइट जैसी भरोसेमंद जगहों से जानकारी लें। साथ ही यह भी कहा है कि अगर आपको कोई मैसेज गलत लगे तो उसकी शिकायत करें। इससे गलत जानकारी को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक के बारे में महले भी कई अफवाह फैली हैं। जैसे कि नोटों को बंद करने या उन्हें बदलने की अफवाहें। रिजर्व बैंक हमेशा कहता है कि अगर कोई भी नियम बदलेगा तो वह औपचारिक तरीके से बताया जाएगा। रिजर्व बैंक ने हमेशा कहा है कि कोई भी नीतिगत बदलाव औपचारिक माध्यमों से ही किया जाएगा। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और हमेशा सही जानकारी के लिए सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें।